दृष्टि
The Vision

करेंट अफेयर्स झारखंड

जुलाई 2022

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोनः 8750187501
ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

झारखंड **3**

- IIT, ISM ने स्मार्ट ऑटो-सिंचाई और मृदा निगरानी प्रणाली विकसित की 3
- लगभग 512 करोड़ रुपए की 224 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास 3
- सौर ऊर्जा नीति, 2022 4
- मुख्यमंत्री ने 251 योजनाओं की रखी आधारशिला, 17 योजनाओं का किया उद्घाटन 4
- 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में झारखंड दसवें स्थान पर 5
- नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड देशभर में अव्वल 5
- ग्रामीण छात्रों को शिक्षित करने के लिये ICFAI ने शुरू की 'विद्या दान' पहल 6
- प्रधानमंत्री ने बाबा नगरी देवघर से झारखंड को दी विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात 6
- समर अभियान के अंतर्गत कुपोषण एवं एनीमिया जाँच के लिये आँगनबाड़ी केंद्र पर चलेगा विशेष अभियान 7
- झारखंड मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 8
- राज्य के विश्वविद्यालयों में एनईपी लागू करने के लिये ड्राफ्ट तैयार 9
- कृषि मंत्री ने किया 24×7 पेट क्लिनिक का उदघाटन 10
- इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड को मिला 10वाँ स्थान 10
- झारखंड की नयी पर्यटन नीति 11
- पोस्टकार्ड फ्रॉम झारखंड' 11
- मुख्यमंत्री सारथी-योजना 12
- मुख्यमंत्री सारथी-योजना 12
- मुख्यमंत्री ने राँची के धुर्वा में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का किया शिलान्यास 13

नोट :

झारखंड

IIT, ISM ने स्मार्ट ऑटो-सिंचाई और मृदा निगरानी प्रणाली विकसित की

चर्चा में क्यों ?

30 जून, 2022 को कृषि विज्ञान केंद्र, धनबाद की वैज्ञानिक सीमा सिंह ने बताया कि IIT (ISM), धनबाद ने कोविड-19 से प्रभावित किसानों के संकटग्रस्त परिवारों के लिये कृषि और खेती को प्रेरित एवं संलग्न करने हेतु एक नई स्मार्ट ऑटो-सिंचाई और मृदा निगरानी प्रणाली का उन्नयन विकसित किया है।

प्रमुख बिंदु

- इसका प्रदर्शन कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), धनबाद में IIT, (ISM) धनबाद अनुसंधान दल द्वारा 30 जून, 2022 को किया गया। यह परियोजना केवीके, धनबाद में स्थापित की गई है।
- यह परियोजना आईईईई एचएसी (मानवीय गतिविधि समिति) और आईईईई एसआईजीएचटी (मानवतावादी प्रौद्योगिकी पर विशेष रुचि समूह) का हिस्सा है, जो चयनित विकासशील देशों में एक संस्थान के साथ वर्तमान कोविड-19 स्थिति में सुधार के लिये चुना गया है।
- इस नई उन्नत प्रणाली को चलाने और आय के स्थायी स्रोत के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस नई उन्नत प्रणाली से किसानों को लाभ होगा।
- वैज्ञानिक सीमा सिंह ने बताया कि यह परियोजना उन किसानों या कोविड-19 प्रवासियों की मदद करेगी, जो सिंचाई के अधिक कुशल तरीके से खेती करने में कम कुशल हैं।
- प्रस्तावित प्रणाली को स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करके कृषि भूमि में अनावश्यक जल अपवाह को दूर करने के लिये डिजाइन किया गया है। सेंसर का उपयोग करके तापमान, हवा की गति, धूप की तीव्रता, मिट्टी की नमी, हवा की नमी और पीएच की रीडिंग की लगातार निगरानी की जाती है। सिस्टम में बिजली की आपूर्ति के लिये सौर पैनलों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह अधिक टिकाऊ होगा।
- यह छात्रों द्वारा विकसित एक एंड्रॉइड एप्लिकेशन द्वारा आसानी से प्रबंधित किया जाता है, जो 'एग्रोप्रो 2.0' नाम से Google Play Store पर उपलब्ध होगा। इंटरफेस को न्यूनतम उपयोग के लिये डिजाइन किया गया है, उपयोग में आसान इंटरफेस के साथ अधिकांश कार्य स्वचालित होते हैं, जिन्हें मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।
- नई प्रणाली लागत प्रभावी है और इसे किसान आसानी से वहन कर सकता है। रखरखाव की लागत भी बहुत कम है। सिस्टम कई विशेषताओं के साथ आता है, जिसमें स्वचालित सिंचाई, बहु-भाषा एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से नियंत्रण, किसान-सिंचाई सहायता 24×7 निगरानी आदि शामिल हैं।

लगभग 512 करोड़ रुपए की 224 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2022 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद में लगभग 512 करोड़ रुपए की 224 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 86 करोड़ रुपए की 118 योजनाओं का शिलान्यास और 161.28 करोड़ रुपए की 106 योजनाओं का उद्घाटन किया।
- वही कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित 172 युवक-युवतियों समेत 175 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किया।

नोट :

- गौरतलब है कि राज्य की 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण परिवेश की है। इनमें किसानों और पशुपालकों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनकी आय में बढ़ोतरी के लिये सरकार लगातार कदम उठा रही है।
- मुख्यमंत्री ने 20,146 लाभुकों के बीच करीब 45 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया।
- इसमें महत्त्वपूर्ण रूप से 3665 लाभुकों के बीच 98 करोड़ रूपए का एमटीएस कोल्ड रूम, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत 194 लोगों को लगभग 5.18 करोड़ रुपए की सहायता राशि, 602 लोगों के बीच पीएमईजीपी, एजुकेशन के सीसी और हाउसिंग लोन के रूप में करीब 9.39 करोड़ रुपए, एनआरएलएम के अंतर्गतच क्रियानिधि, सामुदायिक निवेश निधि और कैश क्रेडिट लिंकेज के रूप में 5361 स्वयं सहायता समूहों 30.65 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के 3100 लाभुकों के बीच 37.20 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना- शहर के 487 लाभुकों के बीच 10.95 करोड़ रुपए की राशि/परिसंपत्ति वितरित की गई।
- इसके अलावा लाभुकों को सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और ग्रीनकार्ड समेत कई और योजनाओं का लाभ दिया गया।

सौर ऊर्जा नीति, 2022

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार हेतु सौर ऊर्जा नीति, 2022 लागू की गई, जिसके तहत सौर ऊर्जा से 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिये निर्धारित है।

प्रमुख बिंदु

- सोलर पार्क, कैनाल टॉप सोलर, फ्लोटिंग सोलर जैसी कई योजनाओं के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा के विकास हेतु विस्तृत नीति बनाई गई है।
- अगले 5 वर्षों में राज्य में समेकित रूप से लगभग 4,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के अधिष्ठापन का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके तहत यूटिलिटी स्केल पर लगभग 3,000 मेगावाट, डिस्ट्रिब्यूटेड सोलर ऊर्जा के अंतर्गत 720 मेगावाट एवं ऑफग्रिड सोलर प्रोजेक्ट के तहत 280 मेगावाट के सोलर ऊर्जा प्लांट अधिष्ठापन का लक्ष्य तय किया गया है।
- नई नीति में निजी निवेशकों के प्रोत्साहन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम, पेमेंट मैकेनिज्म, लैंड बैंक के माध्यम से भूमि व्यवस्था समेत अन्य प्रावधान किये गए हैं।
- समर्पित सौर ऊर्जा सेल, अधिकतम 60 दिनों के अंदर वैधानिक स्वीकृति 1,000 सोलर ग्राम के गठन की योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने की योजना की नीति के तहत क्रॉस सब्सिडी तथा थर्ड पार्टी और कैप्टिव उपयोग में छूट, 1% की दर से 25 वर्ष तक इंडेक्सेशन, बिजली बिल में छूट, 5 वर्ष तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर में 100% की छूट होगी।
- सरकार द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कार्यों के विश्लेषण हेतु दो उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने 251 योजनाओं की रखी आधारशिला, 17 योजनाओं का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

6 जुलाई, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा कॉलेज, गोड्डा में राज्य सरकार की महत्त्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 00 लाख रुपए की लागत से बने नए समाहरणालय का उद्घाटन एवं 5801.90 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गोड्डा पुलिसलाइन का शिलान्यास किया।
- मुख्यमंत्री द्वारा कुल 17 योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनकी कुल लागत 80 लाख रुपए है, वहीं उन्होंने 251 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 15397.84 लाख रुपए है।

नोट :

- इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 1345 लाभुकों के बीच सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 28 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रखंड और पंचायतों में भी मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, जिनमें निजी विद्यालयों की तरह सभी सुविधाएँ मिलेंगी।

'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में झारखंड दसवें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2022 को जारी 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' के पहले संस्करण में झारखंड पूरे देश में दसवें स्थान पर है। इस सूचकांक में ओडिशा पहले स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' का पहला संस्करण जारी किया।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों में 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में ओडिशा 836 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 0.797 स्कोर के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश 0.794 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों में 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में झारखंड 754 स्कोर के साथ दसवें स्थान पर है।
- विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा 788 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 0.758 स्कोर के साथ दूसरे और सिक्किम 0.710 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- इसके अलावा तीन केंद्रशासित प्रदेशों में, जहाँ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) नकद संचालित है, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव 802 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर हैं।
- यह सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में एनएफएसए के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति और प्रगति का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है।
- यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किये गए सुधारों पर प्रकाश डालता है तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस-लर्निंग वातावरण और स्केल-अप सुधार उपायों का निर्माण करता है।
- वर्तमान सूचकांक काफी हद तक एनएफएसए वितरण पर केंद्रित है और इसमें भविष्य में खरीद, पीएमजीकेएवाई वितरण शामिल होगा।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिये सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है, जो टीपीडीएस के माध्यम से एनएफएसए के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन को कवर करता है। ये स्तंभ हैं- i) एनएफएसए- कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान, ii) डिलीवरी प्लेटफॉर्म, और iii) पोषण संबंधी पहल।

नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड देशभर में अव्वल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के तहत जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन ने बताया कि रूर्बन मिशन में लगातार बेहतर कार्य किया जा रहा है एवं राज्य स्तर पर कार्य प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने संबंधित जिलों के अधिकारियों को राज्य के विकास के लिए और अधिक तत्परता से विकासोन्मुखी कार्यों पर जोर देने का निर्देश दिया।

नोट :

- मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) ने जून माह की डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें झारखंड देशभर में पहले पायदान पर है। ओवर ऑल परफार्मेंस में भी झारखंड ने सुधार करते हुए देशभर में 8वाँ स्थान अर्जित किया है। भविष्य में रूर्बन मिशन से हर गाँव-हर परिवार को लाभान्वित करना राज्य सरकार का लक्ष्य है।
- इसी के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीणों को रोज़गार उपलब्ध कराने की पहल की गई है। इस कार्य में रूर्बन योजना प्रभावी भूमिका निभा रही है। रूर्बन योजना का उद्देश्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर फोकस करना है, आर्थिक विकास और मूल्य सृजन, ईएनटी बढ़ाने तथा बुनियादी सेवाओं के साथ-साथ सिंचाई सुविधा के लिये कुआँ इत्यादि के निर्माण पर जोर देना है।

ग्रामीण छात्रों को शिक्षित करने के लिये ICFAI ने शुरू की 'विद्या दान' पहल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, रांची परिसर में झारखंड के पड़ोसी गाँवों के ग्रामीण छात्रों के शिक्षा स्तर में सुधार के लिये 'विद्या दान' नामक एक अभिनव पहल शुरू की गई।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में आईसीएफएआई के कुलपति प्रोफेसर ओ.आर.एस. राव ने कहा कि भारत सरकार की उन्नत भारत अभियान (यूबीए) योजना के तहत विश्वविद्यालय ने पाँच पड़ोसी गाँवों, सिमलिया, दलदली, गुटुआ, तिलटा और पुंदाग को गोद लिया था।
- इन पाँच गाँवों में एक सर्वेक्षण करने के बाद ग्रामीण छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता और आईटी कौशल में सुधार के लिये 'विद्या दान' योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत विश्वविद्यालय परिसर में शाम 4.30 बजे से गणित और भौतिकी में कक्षा 8 के छात्रों के लिये उपचारात्मक कक्षाएँ आयोजित की जाएंगी।
- इसके अलावा 5 पंचायतों में विद्या दान केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें युवाओं को आईटी कौशल में प्रशिक्षित करने के लिये कंप्यूटर केंद्र स्थापित की जाएंगी।
- प्रोफेसर राव ने कहा कि एक चलित पुस्तकालय स्थापित करने की भी योजना बनाई जा रही है, जिसमें पाठ्य-पुस्तकों और कहानी की किताबों की मोबाइल लाइब्रेरी वाला एक वाहन सभी 5 गाँवों की यात्रा करेगा।

प्रधानमंत्री ने बाबा नगरी देवघर से झारखंड को दी विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर से 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री ने बाबा वैद्यनाथ धाम को सीधा हवाई संपर्क प्रदान करने के लिये 401 करोड़ रुपए की लागत से बने देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 657 एकड़ में फैला देवघर एयरपोर्ट राँची के बाद झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन की क्षमता सालाना लगभग पाँच लाख यात्रियों की है।
- प्रधानमंत्री ने इंडिगो कंपनी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ) रोनो दत्ता और चीफ ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन आशू मिश्रा को उड़ान ध्वज प्रदान कर देवघर-कोलकाता-देवघर विमान सेवा का शुभारंभ किया।
- प्रधानमंत्री ने एम्स, देवघर रोगी (इन-पेशेंट) विभाग (आईपीडी) और ऑपरेशन थिएटर संबंधी सेवाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं। यह प्रधानमंत्री के देश के सभी हिस्सों में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के विज़न के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने 25 मार्च, 2018 को एम्स देवघर की आधारशिला रखी थी।

नोट :

- प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई परियोजनाओं में 2,000 तीर्थयात्रियों की क्षमता वाले दो बड़े तीर्थमंडली भवनों का विकास, जलसर झील के फ्रंट का विकास, शिवगंगा तालाब विकास आदि शामिल हैं। नई सुविधाओं से हर साल बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के अनुभव में सुधार होगा।
- प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कई सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में संपर्क को और प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही आम जनता के लिये आवाजाही आसान हो जाएगी।
- प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की विभिन्न एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसमें गेल की जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइपलाइन का बोकारो-अंगुल खंड; बरही, हज़ारीबाग में एचपीसीएल का नया एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और बीपीसीएल के बोकारो एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र का लोकार्पण शामिल हैं। इसके अलावा झरिया ब्लॉक में पर्बतपुर गैस कलेक्टिंग स्टेशन, ओएनजीसी के कोल बेड मीथेन (सीबीएम) एसेट का शिलान्यास किया गया।
- प्रधानमंत्री ने दो रेल परियोजनाओं- गोड्डा-हंसडीहा विद्युतीकरण खंड और गरहवा-महुरिया दोहरीकरण परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से उद्योगों और बिजलीघरों को सामान की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। इनसे दुमका से आसनसोल के बीच ट्रेनों की आवाजाही भी आसान हो जाएगी।
- प्रधानमंत्री ने तीन रेल परियोजनाओं- राँची रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, जसीडीह बाइपास लाइन और एलएचबी कोच रख-रखाव डिपो, गोड्डा का शिलान्यास भी किया। इनमें राँची स्टेशन के पुनर्विकास में फूड कोर्ट, एग्जीक्यूटिव लॉउंज, कैफेडेरिया, एयर कंडीशंड वेटिंग हॉल आदि सहित विश्वस्तरीय यात्री सुविधाएँ शामिल हैं। इससे आवाजाही आसान होने के साथ ही यात्रियों के लिये आराम भी सुनिश्चित होगा।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 वर्षों में हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम के माध्यम से लगभग 70 नए स्थान जोड़े गए हैं। आज आम नागरिकों को 400 से अधिक नए रूटों पर हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है।
- 2014 से पहले भारत में 74 हवाई अड्डे थे, लेकिन सात वर्षों में अप्रैल 2022 तक कुल 140 हवाई अड्डों (हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम सहित) को लेकर 66 नए हवाई अड्डे स्थापित किये गए हैं।
- उड़ान (UDAN) योजना के तहत जून 2022 तक 420 से अधिक हवाई मार्ग परिचालित किये गए। इस योजना के तहत 1.79 लाख से अधिक उड़ानें भरी गई हैं। उड़ान योजना ने पहाड़ी राज्यों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और द्वीपों सहित अखिल भारतीय कई क्षेत्रों को अत्यधिक लाभान्वित किया है।

समर अभियान के अंतर्गत कुपोषण एवं एनीमिया जाँच के लिये आँगनबाड़ी केंद्र पर चलेगा विशेष अभियान

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2022 को झारखंड राज्य पोषण मिशन के महानिदेशक राजेश्वरी बी ने राज्य के 5 ज़िलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर 15 जुलाई से 31 जुलाई, 2022 तक पंचायत एवं प्रखंडवार संदिग्ध कुपोषण एवं एनीमिया वाले बच्चों एवं महिलाओं की जाँच के लिये समर अभियान के तहत एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- यह विशेष अभियान प्रदेश के पाँच ज़िलों- लातेहार, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा एवं साहिबगंज में चलाया जाएगा।
- राजेश्वरी बी ने कहा कि 5 जुलाई, 2022 को समर अभियान की प्रगति पर की गई समीक्षा में यह पाया गया कि लगभग 20,492 कुपोषण एवं एनीमिया के संदिग्ध मामले राज्य में हैं, जिनमें से अब तक केवल 641 की जाँच आँगनबाड़ी केंद्रों पर की गई है।
- कुल 19,851 कुपोषण एवं एनीमिया के संदिग्ध मामलों की जाँच की जानी है। इस हेतु 15 से 31 जुलाई, 2022 तक विशेष अभियान चलाकर कुपोषण एवं एनीमिया की जाँच का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
- कुपोषण व एनीमिया के सभी मामले की सूची SAAMAR App में आँगनबाड़ी केंद्र पर होने वाली जाँच पर उपलब्ध है। आँगनबाड़ी सेविका यह सुनिश्चित करेंगी कि पोषण ट्रैकर में पूर्व से चिह्नित अति गंभीर कुपोषित बच्चे की सूचना SAAMAR APP में संकलित कर ली जाए। आँगनबाड़ी गाँव स्तर पर प्रत्येक दिन कैंप लगाकर ए.एन.एम. की उपस्थिति में सभी संदिग्ध मामलों में कुपोषण (वज़न, लंबाई, ऊँचाई, चिकित्सकीय जाँच, भूख की जाँच) एवं एनीमिया की जाँच सुनिश्चित की जाएगी।

नोट :

- उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रतिदिन की प्रगति प्रतिवेदन समर डैश बोर्ड पर संकलित हो और प्रत्येक सप्ताह उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर वस्तुस्थिति की समीक्षा की जाए।
- 6 माह से 5 वर्ष तक के अति गंभीर कुपोषण से ग्रसित बच्चों (SAM), जिनमें कोई चिकित्सीय बीमारी नहीं है एवं वह बच्चा भूख की जाँच में पास है, का उपचार कम-से-कम 4 माह तक समुदाय आधारित प्रबंधन आँगनबाड़ी केंद्र (SAM) में 11 चरण को अपनाते हुए किया जाएगा।
  - चरण-1 : सामुदायिक गतिशीलता
  - चरण-2 : संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग व शारीरिक नाप
  - चरण-3 : अति गंभीर कुपोषित बच्चों का चिकित्सकीय आकलन
  - चरण-4 : अति गंभीर कुपोषित बच्चों की भूख की जाँच करना
  - चरण-5 : STC में रखना चाहिये या MTC को रेफर करना चाहिये
  - चरण-6 : पोषणात्मक उपचार
  - चरण-7 : SAM KIT (दवाईयाँ)
  - चरण-8 : पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
  - चरण-9 : बच्चों का फालोअप
  - चरण-10 : डिस्चार्ज देने के मापदंड
  - चरण-11 : डिस्चार्ज पाने के बाद फालोअप
- जन्म से 6 माह तक के अति गंभीर कुपोषण से ग्रसित बच्चों (SAM) का उपचार कुपोषण उपचार केंद्र पर किया जाएगा।
- जन्म से 5 वर्ष तक के अति गंभीर कुपोषण से ग्रसित बच्चों (SAM), जिनमें कोई चिकित्सीय बीमारी है एवं वह बच्चा भूख की जाँच में फेल है, का उपचार कुपोषण उपचार केंद्र पर किया जाएगा।
- एनीमिया से ग्रसित बच्चे/किशोरी/युवती एवं गर्भवती महिलाओं का उपचार एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किया जाएगा।

झारखंड मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

15 जुलाई, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद की बैठक में निजी क्षेत्र में 40 हज़ार रुपए सेलरी तक की नियुक्तियों में स्थानीय लोगों के लिये 75 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।
- मंत्रिपरिषद ने राज्यकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय कमेटी के गठन का निर्णय किया। इस कमेटी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव सदस्य होंगे। इस कमेटी की अनुशंसा पर ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का मसौदा तैयार होगा।
- मंत्रिपरिषद ने उन कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक दिसंबर 2004 (नई पेंशन योजना के लागू होने की तिथि) तक पूरी हो चुकी थी, लेकिन जिन्हें नियुक्ति-पत्र नहीं मिल सका था।
- इसके साथ ही पूर्व से संचालित केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण योजना-0 के अंतर्गत केंद्र सरकार के अगले आदेश तक अवधि विस्तार की मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी।
- मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि राज्य में 100 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले को मुफ्त बिजली मिलेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ऐसे करीब 31 लाख 52 हज़ार 773 उपभोक्ता हैं, जो 100 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ होगा।

नोट :

- मंत्रिपरिषद ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके के सेवानिवृत्त शिक्षकों/वैज्ञानिकों/ पदाधिकारियों-निदेशक, अधिष्ठाता, कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पेंशनरों को सातवीं पुनरीक्षित पेंशन दिनांक 01.2016 के प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति दी गई।
- मंत्रिपरिषद के अन्य निर्णय-
  - अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
  - डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों के विद्यमान पदों का युक्तिकरण एवं नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  - पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई।
  - रामगढ़ ज़िले में एक कुटुंब न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई।
  - खूँटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और पलामू में खुले 8 नए पॉलीटेक्निक कॉलेजों के संचालन का जिम्मा प्रेझा फाउंडेशन को दिया गया है।
  - राज्य मंत्रिपरिषद ने वित्त विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत 505 पुराने पदों को सरेंडर किया गया है और 515 नए पद सृजित किये गए हैं।
  - राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि ताना भगतों को साल में दो बार कपड़े खरीदने के लिये चार हज़ार रुपए वार्षिक दिये जाएंगे। यह लाभ 25 वर्ष से अधिक उम्र के सभी ताना भगतों को मिलेगा।
- मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को 1 किलो चना दाल हर माह एक रुपए की दर पर देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जन-वितरण प्रणाली के तहत राशनकार्डों में संशोधन के लिये सरलीकरण की प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य के विश्वविद्यालयों में एनईपी लागू करने के लिये ड्राफ्ट तैयार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड राज्य सरकार द्वारा यूजीसी की ओर से एनईपी लागू करने के लिये दिये गए प्रारूप के आधार पर राज्य के सभी सात विश्वविद्यालयों में इसी अकादमिक सत्र से नई शिक्षा नीति-2022 (एनईपी) लागू करने के लिये ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके अनुसार स्नातक अब चारवर्षीय होगा। साथ ही एक वोकेशनल विषय पढ़ना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोर में दो नए अनिवार्य विषय शामिल किये गए हैं।
- ड्राफ्ट उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सौंपा जाना है। इस पर स्वीकृति मिलने के बाद सभी विश्वविद्यालय सिलेबस तैयार कर सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे, जिसके बाद यह चांसलर पोर्टल पर डाला जाएगा।
- गौरतलब है कि उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की ओर से राज्य के विश्वविद्यालयों में एनईपी-2022 लागू करने के लिये एक कमेटी गठित की गई थी, जिसकी बैठक 2 से 14 जुलाई तक चली।
- प्रारूप के तहत चारवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम 160 क्रेडिट का होगा, प्रति सेमेस्टर 20 क्रेडिट होंगे। तीन सेमेस्टर तक वोकेशनल का एक विषय और कोर के दो नए विषय पढ़ना अनिवार्य होगा। इसके बाद जिस विषय में प्रदर्शन अच्छा होगा, उसी में आगे की पढ़ाई विद्यार्थी कर सकेंगे।
- विषयों को बहुविषय (मल्टीडिसिप्लीनरी) बनाया गया है। कोर में जो दो नए विषय जुड़ने जा रहे हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया और मैथेमेटिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग शामिल हैं।
- वोकेशनल विषयों में बीबीए, बीसीए, हेल्थ एंड हाइजीन एंड योगा वेलनेस अनिवार्य विषय के रूप में डाले गए हैं। इनमें एक विषय पढ़ना होगा।

नोट :

कृषि मंत्री ने किया 24×7 पेट क्लिनिक का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

19 जुलाई, 2022 को झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने हेसाग, हटिया अंतर्गत नवनिर्मित पशुपालन निदेशालय भवन, ऑडिटोरियम, 24×7 पेट क्लिनिक का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री बादल पत्रलेख ने पशुपालन की गतिविधियों से पशुपालकों, जनप्रतिनिधियों आदि को अवगत कराने के लिये एक कार्यशाला का भी उद्घाटन किया।
- कार्यक्रम में बादल द्वारा राज्य के पशुपालकों के लिये पशुपालन से संबंधित विषय, जैसे- मुर्गीपालन, बकरीपालन, सूकरपालन की मार्ग-दर्शिका एवं राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड से संबंधित नियम-अधिनियम की पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।
- उन्होंने कहा कि पशुपालकों को 24×7 चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये ज़िला पशुपालन कार्यालय, राँची में पेट क्लिनिक की सेवा प्रारंभ की गई है। राजधानी राँची में ज़ल्द ही मॉडल पशु अस्पताल भी खोला जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएँ पशुपालकों को मिलेंगी और राज्य के सभी ज़िलों में 24×7 पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस अवसर पर मंत्री बादल द्वारा कुछ चयनित लाभुकों को कुक्कुट तथा बत्तख की योजनाओं के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। उन्होंने विगत एक वर्ष में अनुकंपा के माध्यम से नियुक्त कर्मियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति-पत्र का वितरण किया।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड को मिला 10वाँ स्थान

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स-2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में झारखंड को 10वाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिये 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
- 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक 01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना (17.66 अंक) दूसरे और हरियाणा (16.35 अंक) तीसरे स्थान पर हैं। झारखंड (13.10 अंक) 10वें स्थान पर है। ओडिशा 11.42 अंक के साथ 16वें और छत्तीसगढ़ 10.97 अंक के साथ 17वें (अंतिम) स्थान पर हैं।
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर 37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड (17.67 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि नगालैंड (11.00 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
- केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ (88 अंक) को शीर्ष स्थान मिला है। इस श्रेणी में दिल्ली (27.00 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि लद्दाख (5.91 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
- रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में स्कूलों के प्रतिशत में लगभग 50 प्रतिशत अंकों का सुधार हुआ है। स्कूलों में आइसीटी लैब 23 प्रतिशत से बढ़कर 73 प्रतिशत हो गई हैं। पीएचडी में नामांकन भी बढ़ा है। हालाँकि, मामूली सुधार के साथ छात्र-शिक्षक अनुपात 60:1 है।
- जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य का एफडीआई प्रवाह भी लगभग 8 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है। झारखंड के संबंध में रिपोर्ट कहती है कि महत्त्वपूर्ण औद्योगिक राज्य होने के नाते झारखंड इनोवेशन में रैंकिंग में ऊपर जाने की क्षमता रखता है।
- उल्लेखनीय है कि नीति आयोग और प्रतिस्पर्द्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक माध्यम है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के क्रम में रखता है, ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा बनी रहे।

नोट :

- इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज़ पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमश अक्टूबर 2019 तथा जनवरी 2021 में जारी किये गए थे।

झारखंड की नयी पर्यटन नीति

चर्चा में क्यों ?

24 जुलाई, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नयी दिल्ली में झारखंड की नयी टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने झारखंड की इस नयी टूरिज्म पॉलिसी के तहत निवेशकों को स्पेशल पैकेज उपलब्ध कराए जाने की बात की है जिसके तहत राज्य सरकार निवेशकों को 'First cum first serve' के आधार पर स्पेशल पैकेज देगी। साथ ही निवेशकों को कई तरह के Incentives भी दिये जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत निम्न लाभ दिये जाएंगे -
- Capital Investment पर 10 करोड़ की limit तक 20-25% सब्सिडी दी जा रही है।
- 5 वर्षों तक Net SGST का 75% की छूट दी जाएगी।
- 5 वर्षों तक Stamp Duty और Electricity Duty नहीं लगेगी।
- महिलाओं, SC, ST एवं दिव्यांगों के लिये नीति में विशेष व्यवस्था की गई है।
- निवेश और Incentives के लिये Single Window System बनाया गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि नयी टूरिज्म पॉलिसी के तहत धार्मिक पर्यटन स्थलों देवघर, पारसनाथ, मधुबन और इटखोरी जैसे धार्मिक स्थलों में नागरिक सुविधाएँ प्रदान किये जाने के अलावा उनका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा।
- इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन गतिविधियों को प्रकृति के साथ जोड़ते हुए लातेहार-नेतरहाट-बेतला, चांडिल-दलमा-मिर्चैया-गेटेलसुद इको-सर्किट के विकास का कार्य प्रगति पर है। इन जगहों पर पर्यटकों के रहने के लिये रेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य की वैभवशाली संस्कृति का अनुभव राज्य की जीवंत और विविध संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिये फूड फेस्टिवल, इंटर स्टेट कल्चरल प्रोग्राम आयोजित करने पर ज़ोर दिया जा रहा है।
- ग्रामीण पर्यटन की क्षमता को बढ़ाने के लिये चिह्नित गाँवों का सौंदर्यीकरण, स्थानीय व्यंजनों तथा ग्रामीण जन जीवन को बढ़ावा देना शामिल हैं। इस संबंध में ग्राम पर्यटन समितियों (वीटीसी) और ग्रामीण पर्यटन उपसमिति का गठन किया जाएगा।
- राज्य की पर्यटन पॉलिसी में राज्य की खनिज संपदा को प्रदर्शित करने और खनन पर्यटन के ज़रिये संभावनाओं को तलाशा जाएगा।
- नयी पर्यटन नीति में एडवेंचर टूरिज्म की गतिविधियों जैसे पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग आदि को बढ़ावा देना जैसे कार्य शामिल होंगे। वाटर स्पोर्ट्स के लिये तिलैया, मसनजोर, चांडिल, पतरातू, गेतालसूद, केलाघघ, कांके, हटिया जैसे डैम को विकसित करने की योजना है

पोस्टकार्ड फ्रॉम झारखंड'

चर्चा में क्यों ?

23 जुलाई, 2022 को झारखंड पर्यटन नीति, 2021 के शुभारंभ के साथ 'पोस्टकार्ड ऑफ झारखंड'वृत्तचित्र श्रृंखला का प्रीमियर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल इंडिया पर किया गया।

प्रमुख बिंदु

- झारखंड पर्यटन नीति, 2021 के लॉन्च इवेंट में आधिकारिक तौर पर कुछ माह पूर्व राज्य सरकार और नेशनल ज्योग्राफिक इंडिया के बीच संपन्न एमओयू (MoU) के तहत इसे जारी किया गया।

नोट :

- झारखंड की समृद्ध विरासत को पर्यटन के क्षेत्र में विश्वपटल पर लाने और राज्य की प्राकृतिक संपदा, परंपरा और संस्कृति की अविस्मरणीय झाँकी को प्रस्तुत करने के लिये यह महत्त्वपूर्ण पहल की गई है।
- इस श्रृंखला के माध्यम से नेशनल ज्योग्राफिक इंडिया मैकलुस्कीगंज, नकटा पहाड़, नेतरहाट, दलमा पहाड़ियों की आकर्षक श्रृंखला, लोध फॉल, हुंडरू फॉल, बेतला नेशनल पार्क से लेकर देवरी मंदिर, सूर्य मंदिर और बैद्यनाथ धाम जैसे मंदिरों की अद्भुत झाँकी दिखाएगा।
- लुभावनी सिनेमैटोग्राफी में मनोरम, हरे-भरे जंगल, शानदार वन्य जीवन, हिल स्टेशन और दिल को छू लेने वाले रोमांच के साथ राज्य भर में मौजूद विभिन्न स्थलों की खोज करते हुए अपनी आध्यात्मिक और मनमोहक यात्रा साझा की जाएगी।
- प्रागैतिहासिक पाषाण कला से लेकर शानदार मंदिरों और प्राचीन स्मारकों पर फिल्म के ज़रिये प्रकाश डाला जाएगा।
- इस वृत्तचित्र श्रृंखला की सूत्रधार जमशेदपुर में जन्मी फिल्म अभिनेत्री रसिका दुग्गल है। वे दर्शकों को झारखंड के आदिवासी नृत्य, सोहराई पेंटिंग, स्थानीय व्यंजनों और राज्य के स्थापत्य कला के साथ समृद्ध आदिवासी परंपराओं से परिचित कराएंगी।

मुख्यमंत्री सारथी-योजना

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिविल सेवा परीक्षा-2021 में सफल हुए झारखंड के उम्मीदवारों के लिये आयोजित बधाई समारोह में कहा कि राज्य में जल्द ही 'मुख्यमंत्री सारथी-योजना'की शुरुआत की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना आरंभ करने की घोषणा की गई थी।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार सभी वर्ग/समुदाय के वैसे अभ्यर्थी, जो यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये कोचिंग के खर्च का वहन नहीं कर पा रहे हैं, को अपने खर्चे से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाएगी।
- गौरतलब है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2021 में झारखंड के 26 उम्मीदवार सफल हुए हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जहाँ विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति दी जा रही है। आने वाले समय में राज्य सरकार बच्चों के विदेश जाने का यह दायरा बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री सारथी-योजना

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिविल सेवा परीक्षा-2021 में सफल हुए झारखंड के उम्मीदवारों के लिये आयोजित बधाई समारोह में कहा कि राज्य में जल्द ही 'मुख्यमंत्री सारथी-योजना'की शुरुआत की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना आरंभ करने की घोषणा की गई थी।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार सभी वर्ग/समुदाय के वैसे अभ्यर्थी, जो यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये कोचिंग के खर्च का वहन नहीं कर पा रहे हैं, को अपने खर्चे से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाएगी।
- गौरतलब है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2021 में झारखंड के 26 उम्मीदवार सफल हुए हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जहाँ विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति दी जा रही है। आने वाले समय में राज्य सरकार बच्चों के विदेश जाने का यह दायरा बढ़ाएगी।

नोट :

मुख्यमंत्री ने राँची के धुर्वा में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का किया शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने, निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राजधानी राँची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु

- वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शिलान्यास समारोह में जुडको और सिडबी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इसके ज़रिये राज्य में औद्योगिक संरचना को विकसित करने और उद्योग लगाने वालों को सिडबी के द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण में जुडको परियोजना के निष्पादन के लिये एक तकनीकी और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेषकर निर्यात संवर्धन से संबंधित तमाम गतिविधियाँ एक ही छत के नीचे संचालित होंगी। यह सेंटर यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
- राज्य सरकार ने निर्यात संबंधी गतिविधियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये राज्य निर्यात संवर्धन समिति और ज़िला निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया है।
- विदित है कि झारखंड देश में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है, जिसका देश के कुल उत्पादन में4% हिस्सा है। वर्ष 2020-21 में राज्य से कुल निर्यात 1,622.31 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। राज्य से निर्यात 2021-22 (फरवरी 2022 तक) में 2,201.55 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- राज्य से निर्यात की जानेवाली प्रमुख वस्तुओं में लोहा, इस्पात, ऑटो पार्ट्स, लोहा और इस्पात के उत्पाद हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड से लौह और इस्पात का कुल निर्यात367 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कुल निर्यात का 62.1% रहा। लाख का उत्पादन करने वाले कुल 5 राज्यों में से 53% उत्पादन झारखंड करता है।
- झारखंड से निर्यात का 32% दक्षिण एशियाई देश, जैसे- बांग्लादेश, नेपाल को जाता है। राज्य का 25% निर्यात दक्षिण-पूर्व एशियाई बाज़ारों में जाता है। इसमें वियतनाम सबसे ऊपर है। 13% निर्यात इटली जैसे यूरोपीय देशों और 11% चीन जैसे पूर्वी एशियाई बाज़ार में किया जाता है।
- वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की खासियत-
- वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएँ एक ही परिसर में मिलेंगी।
- इस सेंटर में व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिषद से जुड़े कार्यालय होंगे। इसके अलावा आयात-निर्यात से जुड़ी कंपनियों के लिये स्थान मुहैया कराया जाएगा। यहाँ करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफर तक की सुविधाएँ मिलेंगी।
- वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से होगा। यह45 एकड़ भूमि में बनेगा। इसकी कुल परियोजना लागत 44.59 करोड़ रुपए होगी।
- यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने वाली कंपनियों को उनके उत्पादों के प्रदर्शन और उनके प्रचार-प्रसार के लिये भी जगह उपलब्ध कराई जाएगी।
- वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कृषि और खाद्य उत्पाद, वस्त्र, तसर उत्पाद तथा इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण 2 सालों में पूरा होगा। यहाँ बहुउद्देशीय सम्मेलन कक्ष, सेमिनार हॉल, आयात-निर्यात बैंक के अलावा कई और सुविधाएँ होंगी।

नोट :